बिश्केक में भारत की स्थिति

लेखक - पी. स्टोबदान (पूर्व भारतीय राजदूत, किर्गिस्तान गणराज्य)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र- II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

13 जून, 2019

"मध्य एशियाई देशों की क्षेत्रीय आकांक्षाएँ भारत के लक्ष्यों के विपरीत हैं।"

किर्गिस्तान के बिश्केक में 19वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ, SCO) शिखर सम्मेलन में भारत को दो विरोधाभासी अनिवार्यताओं के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। जहाँ एक ओर इसे चीन और रूस के नेतृत्व में क्षेत्रीय सहयोग के इच्छुक भागीदार के रूप में काम करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर इसे 'अमेरिकी-विरोधी गिरोह' के एक हिस्से के रूप में प्रतीत होने से बचना चाहिए। इसे एक विरोधाभास के रूप में भी देखा जा सकता है कि भारत एक ऐसे निकाय के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहता है जिसमें ऐसे देश शामिल हैं, जो भारतीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।

व्यापार और आतंकवाद

बिश्केक में, रूस और मध्य एशियाई देशों को अमेरिका के खिलाफ अपनी बढ़ती टैरिफ युद्ध में चीन के लिए 'व्यापक समर्थन' व्यक्त करने की संभावना है। भारत इस व्यापार युद्ध के बारे में समान रूप से चिंतित है, लेकिन इसने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वह अमेरिकी संरक्षणवाद का नारा लगाने में दूसरों के साथ शामिल होगा। नई दिल्ली को चीन के समर्थन के बिना अमेरिका के साथ व्यवहार करने के बारे में विश्वास है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए, अमेरिका-विरोधी होना, उनके भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान और सत्ता की एकाग्रता के खिलाफ बढ़ते विरोध को शांत करने का काम करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के सभी एससीओ सदस्य बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के उत्साही समर्थक हैं।

शिखर सम्मेलन में एक मौन एजेंडा होने की संभावना है। एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने बहुपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए दस्तावेजों को अपनाने और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई, आईटी में सहयोग, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सेवा जैसे गैर-पारंपरिक मुद्दों पर चर्चा करने का संकेत दिया है।

आतंकवाद के मुद्दे को अफगानिस्तान में स्थिति को सुधारने के दृष्टिकोण से संबोधित किया जा सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान से निकलने वाले आतंकवादी तत्वों पर अंकुश लगाने के मुद्दे पर कम ध्यान दिए जाने की संभावना बढ़ जाती है। चीन को आतंकवाद से निपटने के अपने अनुभवों की पेशकश करना सुनिश्चित है। जहाँ शिनजियांग में किए गए प्रयासों का उदहारण दिया जा सकता है। अशांत शिनजियांग में अपने हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार करने में चीन की उपलब्धि यूरेशिया के लिए भारी आर्थिक और सुरक्षा निहितार्थ के साथ आती है। चीन ने अपने पश्चिमी सीमाओं से परे किसी भी संभावित संकट को पूरा करने के लिए अपनी सैन्य प्रक्षेपण क्षमताओं को भी बढ़ाया है।

किर्गिस्तान ने अभी हाल ही में अलाई जिले में चीन की सीमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार व्यापार केंद्र स्थापित किया है। यदि क्षेत्रीय देश 1,435 मिमी के चीनी रेलवे ट्रैक गेज को अपनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो चीन यूरेशिया को एकजुट करने के लिए एकजुट यूरोप को चुनौती देने में सफल होगा। जैसे-जैसे स्थिति सामने आ रही है, चीन और रूस वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के एक नए युग को अपना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इन सब में भारत कहां फिट बैठता है।

किनारों पर

शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक महत्त्वपूर्ण होगी। विशेष रूप से तब, जब श्री मोदी अपने नए विदेश मंत्री द्वारा निर्देशित किये जा रहे हों। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में वैश्विक

आतंकवादी के रूप में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को सूचीबद्ध करने पर चीन के फैसले के बाद हो रही है। दोनों नेताओं के लिए महत्वपूर्ण चिंता अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का प्रभाव है, लेकिन रुझानों से देखते हुए, दोनों पक्ष लंबित द्विपक्षीय मुद्दों के एक बड़े समाधान के लिए कमर कसते दिख रहे हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ श्री मोदी की बैठक सीएएटीएसए (CAATSA) के तहत कार्य करने के वाशिंगटन के बढ़ते खतरे के खिलाफ एस-400 अनुबंध सौदे को बचाने के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। भारत और रूस के बीच 2019 के लिए एक महत्वाकांक्षी आर्थिक एजेंडा है और श्री पुतिन सितंबर में व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मोदी को अपना निमंत्रण दोहरा सकते हैं।

यह भारत के लिए रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र का पता लगाने के लिए न केवल आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए, बल्कि क्षेत्र में चीनी जनसांख्यिकीय खतरों को दूर करने के लिए कुशल मजदूरों को स्थानांतरित करने की संभावनाओं की खोज के लिए एक अच्छा अवसर होगा। रूस भी चाहता है कि भारत आर्कटिक: टेरिटरी ऑफ डायलॉग फोरम में शामिल हो।

भारत सहकारी और टिकाऊ सुरक्षा ढांचे को विकसित करने, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तथा अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के प्रयासों में भाग लेने के लिए SCO के भीतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भले ही मध्य एशियाई देशों की क्षेत्रीय आकांक्षाएँ भारत के लक्ष्यों के विपरीत हैं, फिर भी ये देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं। श्री मोदी ने पुलवामा और श्रीलंका में हुए हमलों पर एससीओ का ध्यान आकर्षित करके आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प को पूरा करने के दृष्टिकोण को दर्शाया है। लेकिन चीन यह नहीं चाहेगा कि भारत एससीओ का इस्तेमाल पाकिस्तान को बदनाम करने और कमजोर बनाने के लिए करे।

भारत बीआरआई पर अपनी स्थिति पर कायम रह सकता है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे, चाबहार पोर्ट, अश्गाबात समझौते और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर प्रगति को तेज करना होगा।

पाकिस्तान नीति

भारत-पाकिस्तान गतिरोध समाप्त हो सकते थे, लेकिन बालाकोट में भारत के हवाई हमलों के बाद से वातावरण थोड़ा बदल गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कम जुझारू प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी सेना भारत विरोधी आतंकी समूहों पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है या नहीं, इसका पता नहीं है।

श्री खान को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा कि यदि वह चाहते हैं कि श्री मोदी राजनयिक को मौका दें, तो उन्हें एससीओ बैठक पर मिलना चाहिए। श्री मोदी सामान्यीकरण संबंधों के पक्ष में एक नया नीतिगत पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं, खासकर जब से भारत ने मसूद अजहर को UNSC में एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है।

एससीओ द्वारा द्विपक्षीय विवादों पर बहुत कम ध्यान देने के बावजूद पाकिस्तान प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों (अफगानिस्तान और कश्मीर) को विनियमित करने के लिए एससीओ से उच्च उम्मीदें बना रखा है। इसका अन्य एजेंडा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और सुरक्षा सहयोग के लिए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को बढ़ावा देने के अलावा ग्वादर पोर्ट को मध्य एशियाई देशों के लिए एक संभावित मार्ग के रूप में प्रचारित करना है।

निश्चित रूप से, संयुक्त एससीओ सैन्य अभ्यास सहित संस्थागत स्तर के उपायों में से कोई भी अब तक संयुक्त रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला है। फिर भी, एससीओ भारत के लिए प्रासंगिक है ताकि वह यूएनएससी में सुधारों की मांग को अधिक प्रभावी बना सकें एवं अपने पक्ष में समर्थन जुटा सके। भारत लंबे समय से UNSC की गैर-स्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों की उम्मीदवारी को समर्थन दे रहा है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

चर्चा में क्यों?

- किर्गिस्तान के बिश्केक में आज से दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन आयोजित हो रहा है।यह एससीओ का 19वां सम्मेलन है।
- इस समिट के दौरान पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे।
- भू-रणनीतिक संतुलन की दृष्टि से भी देखें तो यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है।
- एससीओ चीन के नेतृत्व वाला आठ सदस्यीय आर्थिक एवं सुरक्षा ब्लॉक है। इस समूह में भारत और पाकिस्तान को साल 2017 में शामिल किया गया था।

क्या है?

- एससीओ एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है।
- इसकी स्थापना 15 जून, 2001 को शंघाई में हुई थी।
- एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 2003 में लागू हआ।
- यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है, जो संगठन के लक्ष्यों व सिद्धांतों आदि के साथ इसकी संरचना तथा प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है।
- रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएँ हैं।

गठन:-

- वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान 'शंघाई-5' नामक संगठन के सदस्य थे।
- वर्ष 1996 में 'शंघाई-5' का गठन विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं से हुआ था, जो चीन के साथ चार पूर्व सोवियत गणराज्यों ने सीमाओं पर स्थिरता के लिये किया था।
- वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद 'शंघाई-5' को SCO नाम दिया गया।
- वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला।

सदस्य देश:-

- वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं।
- अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देशों में शामिल हैं।
- अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका इस संगठन के वार्ता साझेदार देश हैं।

लक्ष्य:-

- सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मजबूत करना।
- राजनैतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
- शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, इत्यादि में क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना।
- संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना तथा सुनिश्चिता प्रदान करना।
- एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव-अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।

संरचना

- **राष्ट्र प्रमुखों की परिषद:** यह SCO का सर्वोच्च निकाय है, जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से तथा बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है।
- **शासन प्रमुखों की परिषद:** SCO के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है तथा संगठन के बजट को मंजूरी देती है।
- **विदेश मंत्रियों की परिषद:** यह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।
- **क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना** (RATS-):आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद तथा चरमपंथ से निपटने के मामले देखता है।
- **शंघाई सहयोग संगठन सचिवालय:** यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु बीजिंग में अवस्थित है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **'शंघाई सहयोग संगठन' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**
   1. इसकी स्थापना जून, 2001 को शंघाई में हुई थी।
   2. वर्ष 2017 में भारत एवं पाकिस्तान को संयुक्त रूप से सदस्य बनाया गया।
   3. इसका 19वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?
   - (a) 1 और 2
   - (b) 2 और 3
   - (c) 1 और 3
   - (d) 1, 2 और 3

Q. Consider the following statements related to Shanghai Cooperation Organisation-
1. It was established in shanghai in 2011.
2. In 2017, India and Pakistan were jointly given the membership.
3. Its 19th Summit is organised in Bishkek, Kyrgyzstan.

Which of the above statements are correct?
- (a) 1 and 2
- (b) 2 and 3
- (c) 1 and 3
- (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- शंघाई सहयोग संगठन क्या है? हाल के वर्षों में भारत को इसका सदस्य बनाया गया। यह मध्य एशिया में भारत के आर्थिक व सामरिक हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. What is Shanghai Cooperation Organisation? In recent years India has been given its membership. How will it influence the economic and strategic interests of India in Middle East? Discuss.

(250 Words)

नोट : 12 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Committed